Bank assistance; and

(c) if not, what are the reasons for delay and the progress made so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The water supply & sewerage projects of five major towns of Rajasthan, viz., Kota, Ajmer, Bikaner, Udaipur and Jodhpur submitted by the Government of Rajasthan at an estimated cost of Rs. 2022.17 crores have been approved by this Ministry in principal and recommeded for external assistance.

(b) and (c) There is no Central assistance programme for such projects. Hence, the question of making any budget allocation for 1997-98 or during the Ninth Five Year Plan in the Central budget does not arise. The World Bank has not committed to provide any assistance for this project so far. However, the State Government has informed that a budget provision of Rs. 2.94 crores has been tentatively allocated under the State sector during 1997-98.

इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत नीति खण्ड सेक्टर 3 **में फ़्लैटों के आवंटन हेतु ड्रा**

2859.**श्री मती मालती शर्मा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत नीति खण्ड सेक्टर 3 में डुप्ले फ्लैट्स के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे,यदि हां,तो कुल निर्मित मकानों एंव प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी-कितनी हैं;

(ख) यदि हां,तो क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का मार्च में इन फ्लैटों के आवंटन हेतु ड्रा निकालने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मकानों के लिए आवेदन नहीं मांगे गये थे; यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या उक्त आरक्षित मकानों को आवंटित कर दिया गया हैं ?

शहरी कार्य और रोजागर मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा.यू.वेंकटेस्वरल): (क) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उन्होंने इंन्दिरा-पुरम योजना सैं.3 नीतिखंड में 95 उच्च आय वर्ग डुप्लेक्स मकानों के अवंटन हेतु नवम्बर,1996 में एक स्कीम की घोषणा की थी जिसके लिए जी.डी.ए.को 250 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी,हां।

(ग) जी.डी.ए.ने सूचना दी है कि सभी मकान जो बिक्री के लिए उपलब्ध थे उनको जनता में आवंटन हेतु शामिल कर लिया गया

Housing Shortage in the Country

2860. DR. B.B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the housing shortage at the national level in 1981 and 1991, with urban Rural break-up;

(b) the magnitude of the likely housing shortage by the end of the present century;

(c) in what manner Government propose to meet this shortage;

(d) what are the plans to make available houses to the lower and middle income groups; and

(e) the percentage of total budget (1996-97), total Eight Five Year Plan outlay and the total of GDP (1995-96) spent on housing in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) On the basis of 1981 and 1991 Census data, the periodical estimates of housing shortage made by NBO are as follows:—